

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी-सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 115/2023
अपीलांट

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. जयसिंह पुत्र स्व० बालुराम
2. प्रेमप्रकाश पुत्र स्व० बालुराम
3. विजयसिंह पुत्र स्व० बालुराम
4. खींवरराज पुत्र स्व० बालुराम
5. मोतीसिंह पुत्र स्व० बालुराम
6. डुंगरसिंह पुत्र स्व० बालुराम
7. मुलसिंह पुत्र स्व० बालुराम

(जाति माली, निवासी होली चौक
के पास, नयापुरा, मण्डोर रोड,
जोधपुर)

1. सरिता पत्नी जितेन्द्रसिंह माली
निवासी चैनपुरा, मण्डोर, जोधपुर
2. कुसुम पत्नी कल्याणसिंह माली
3. मोहित पुत्र कल्याणसिंह माली
(निवासी चैनपुरा, मण्डोर, जोधपुर)
4. भैरूसिंह पुत्र खींवरराज माली
निवासी खोडीवाला बेरा, प्रथम
गली, माता का थान रोड, जोधपुर
5. हजारीसिंह पुत्र भेराराम माली
निवासी माता का थान, मगरा
पूजला, जोधपुर
6. पृथ्वीसिंह गहलोट पुत्र किसनलाल
माली, निवासी जालवाला बेरा, न्यु
नागोर रोड, मण्डोर, जोधपुर
7. राज० राज्य जरिये तहसीलदार
जोधपुर



अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश दिनांक
03.03.2023 सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर राजस्व विविध
प्रार्थना पत्र संख्या 148/2022 अनवान सरिता व अन्य बनाम सरकार

उपस्थित-

1. श्री कानाराम गोदारा, वकील अपीलाण्ट
2. श्री अक्षय कुमार दवे, वकील रेस्पो० संख्या 1 से 6
3. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो० संख्या 7

निर्णय

दिनांक 20.11.2025

प्रस्तुत राजस्व अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि
अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी-रेस्पो० सं० 1 से 6-सरिता वगैरा ने प्रार्थना पत्र
अन्तर्गत धारा 111, 128, राज० भू-राजस्व अधि०, 1956 प्रस्तुत कर तहसील जोधपुर
के ग्राम चैनपुरा स्थित अपने खातेदारी खसरा नं० 389 रकबा 6.05 बीघा भूमि की
पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु अप्रार्थी-तहसीलदार जोधपुर के विरुद्ध प्रस्तुत किया।

due
20/11

राजस्थान न्यायालय
जोधपुर

से अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.3.23 द्वारा स्वीकार कर प्राथी-रेस्पों की उल्लेखित खसरान की भूमि के संबंध में नाप व सीमांकन प्रार्थीगण की उपस्थिति में करवाकर, पत्थरगढ़ी करवाने हेतु तहसीलदार जोधपुर को आदेशित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने राज० भू-राजस्व अधि० 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने की अनुमती हेतु अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र मय श०प० प्रस्तुत किया गया, जिसे न्यायहित में स्वीकार कर प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।



बहस सुनी गई। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलांट्स विवादित खसरा नं० 389 के पड़ोसी खसरा नं० 390 का काबिजकाशत खातेदार है व दोनों खसरों के बीच पट्टीया व मुटाम स्थित है। रेस्पों मुटामों को हटाकर ख०नं० 389 व 390 की भूमि पर कब्जा करने की नियत से बिना अपीलांट को पक्षकार बनाये सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी का आदेश पारित करवा लिया गया। ग्राम चैनपुरा के ख०नं० 389 व अन्य भूमि के संबंध में न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर में राजस्व वाद बअनवान शंकरसिंह बनाम कुसुम वगैरा विचाराधीन है। राजस्व रिकॉर्ड में स्व० ओमप्रकाश एवं उनके पुत्रों ने गोरधनराम की झूठी वलियत बताकर राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज दिये और भूमि को हडपने की नियत से बिना अधिकार का बेचान रेस्पों को कर दिया गया। रेस्पों के हक में किये गये बेचाननामे प्रारम्भ से ही शून्य है। वादग्रस्त भूमि पर स्व० ओमप्रकाश को खातेदारी अधिकार हासिल नहीं हुए थे और न ही ओमप्रकाश के उत्तराधिकारियों को खातेदारी हक हासिल हुआ, इसलिए इन्हें भूमि हस्तांतरण का हक अधिकार नहीं था। रेस्पों के हक में निष्पादित बेचाननामों बिना अधिकार वाले व्यक्तियों द्वारा करवाये जाने से उन्हें वादग्रस्त भूमि पर हक अधिकार हासिल नहीं है और न ही इस पर उनका कब्जा है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी-रेस्पों द्वारा उन्हें पक्षकार नहीं बनाये जाने से उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं मिला।

du
 अधिवक्ता सत्यमाव अंगुणा
 जोधपुर

आरएलआर एक्ट की धारा 111 व 128 के प्रावधान अनुसार विना तरमीम/सीमाज्ञान पत्थरगढी नही की जा सकती है व पडौसी खातेदार की उपस्थिति व सुनवाई आवश्यक है। विधि अनुसार प्रकरण में राजस्व नक्शे के अनुसार तरमीम किया जाना आवश्यक है, जो कटा-फटा है। आलौच्य प्रकरण में अप्राथी-तहसीलदार जोधपुर द्वारा प्रस्तुत जवाब में वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की होने व इसके विभाजन के बाद पत्थरगढी संभव होना बताते हुए प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने का आग्रह किया गया। अतः अपीलाधीन आदेश विधिविरुद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 14.05.2017 पेज नं० 289-294 की प्रति प्रस्तुत की गई।



जवाब में रेस्पोंड सं० 1 से 6 के अधिगता द्वारा अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि अपीलांट्स एवं रेस्पोंड की खातेदारी भूमि अलग-अलग है एवं नक्शे में तरमीम सुदा है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी-रेस्पोंड द्वारा तहसील जोधपुर स्थित ग्राम चैनपुरा के रेकर्डेड संयुक्त खातेदारी खसरा नं० 389 का सीमाज्ञान करवाकर पत्थर गढी करवाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया। अतः आलौच्य प्रकरण में अप्राथी-तहसीलदार जोधपुर द्वारा प्रस्तुत जवाब कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से इसके विभाजन के बाद पत्थरगढी संभव होना गलत है, क्योंकि आवेदन संयुक्त भूमि की पत्थरगढी हेतु प्रस्तुत किया गया है, न कि किसी सह-खातेदार द्वारा अपने हक हिस्से तक का। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार जोधपुर की पालना रिपोर्ट क्रमांक 836 दिनांक 27.3.23 के अनुसार अपीलाधीन आदेश की पालना में फर्द सीमांकन पत्थरगढी दिनांक 21.3.23 को हो चुकी है। जमाबंदी संवत् 2061-64 दिनांक 29.12.2005 के अनुसार प्रार्थी-रेस्पोंड के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, अतः वकील अपीलांट द्वारा इनके खातेदारी अधिकारों के संबंध में अपील मीमों में किए गये कथन साबित नहीं है और न ही उनके द्वारा इसके कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत किए गये हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाने का आग्रह किया गया।

du

निरस्त
जोधपुर

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली एवं रेकॉर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार जोधपुर की पालना रिपोर्ट क्रमांक 836 दिनांक 27.3.23 के अनुसार अपीलाधीन आदेश की पालना में फर्द सीमांकन पत्थरगढी दिनांक 21.3.23 को होने का उल्लेख है। जबकि इसके विपरीत उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर) के पत्रांक: 15 दिनांक 25.1.24 के अनुसार वादग्रस्त खसरान की तारबंदी/बाउण्ड्री वाल हेतु दिनांक 30.1.24 नियत कर पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने के लिए पुलिस उपायुक्त (पूर्व) जोधपुर से अपेक्षा की गई है। इसके अलावा आलौच्य प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया जाने से उसे सुनवाई का अवसर नहीं मिला। इस स्थिति में अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है।



अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 148/2022 अनवान सरिता व अन्य बनाम सरकार में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.03.23 निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलाधीन खसरान की भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगढी हेतु अपीलांट एवं रेसपो० तथा अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारान को पक्षकार संयोजित कर उनकी सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर, विधिवत तामिली के पश्चात, तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त कर सीमांकन एवं पत्थरगढी हेतु विधिसम्मत: आदेश पारित करावे।

निर्णय आज दिनांक 20/11/25 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

all

(सुनिता चौधरी)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

जोधपुर
आतिरिक्त संभागीय आयुक्त

जोधपुर